करियर शीट · CAREER SHEET

Tribal Legal Advocate

जनजातीय विधिक अधिवक्ता एक वकील होता है जो आदिवासी समुदायों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है। वह वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) के तहत जल-जंगल-ज़मीन के अधिकारों, पेसा (PESA, 1996) के अंतर्गत ग्राम सभा के स्वशासन,...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/tribal-legal-advocate

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

जनजातीय विधिक अधिवक्ता एक वकील होता है जो आदिवासी समुदायों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है। वह वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) के तहत जल-जंगल-ज़मीन के अधिकारों, पेसा (PESA, 1996) के अंतर्गत ग्राम सभा के स्वशासन, और संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत मिली सुरक्षा को लागू कराने के लिए अदालतों और प्रशासन में आदिवासी लोगों की पैरवी करता है। वह भूमि हस्तांतरण (लैंड एलियनेशन) रोकने, विस्थापन, झूठे मुकदमों और मानवाधिकार हनन के मामलों में मुफ़्त या रियायती विधिक सहायता देता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण, सम्मानजनक पेशा है जो न्याय और गरिमा के लिए समर्पित है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	12वीं के बाद 5-वर्षीय LLB या स्नातक के बाद 3-वर्षीय LLB + बार काउंसिल पंजीकरण
कोर्स अवधि	LLB: 3–5 वर्ष
आरंभिक वेतन	₹15,000–30,000/माह (जूनियर अधिवक्ता)
कार्य-शैली	अदालत में पैरवी, विधिक सहायता व अधिकार-वकालत

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- आदिवासी समुदायों के अधिकारों और सामाजिक न्याय में गहरी रुचि
- ज़मीनी स्तर पर वंचित लोगों के साथ खड़े होकर बदलाव लाने की चाह
- कानून, संविधान और नीति को पढ़ने-समझने का शौक

क्षमताएँ

- तर्कशक्ति और स्पष्ट, प्रभावी बहस करने की क्षमता
- विस्तृत दस्तावेज़, साक्ष्य और कानून का बारीकी से विश्लेषण
- आदिवासी भाषा/बोली व संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता और धैर्य

ज़रूरी कौशल

- वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा और पाँचवीं अनुसूची का व्यावहारिक ज्ञान
- भूमि अभिलेख, राजस्व रिकॉर्ड और वन दावों की जाँच
- मानवाधिकार व संवैधानिक कानून की समझ
- अदालत में याचिका, वाद-पत्र और दलील तैयार करना व पैरवी करना
- ग्राम सभा, दावाकर्ताओं और अधिकारियों से समन्वय व परामर्श
- स्थानीय भाषा में सरल कानूनी जागरूकता व दस्तावेज़ीकरण

4 कैसे पहुँचें

1. 12वीं कक्षा (किसी भी संकाय से) अच्छे अंकों के साथ पूरी करें।
2. CLAT या राज्य/विश्वविद्यालय की विधि प्रवेश परीक्षा दें और 5-वर्षीय एकीकृत LLB (बीए/बीकॉम एलएलबी) में प्रवेश लें; स्नातक के बाद 3-वर्षीय LLB भी विकल्प है।
3. LLB में संवैधानिक कानून, मानवाधिकार व पर्यावरण-वन कानून पर ध्यान दें और आदिवासी अधिकारों पर इंटर्नशिप करें।
4. बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया की अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) पास कर राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराएं।
5. किसी वरिष्ठ अधिवक्ता, विधिक सहायता संस्था (NALSA/DLSA) या आदिवासी अधिकार NGO के साथ अनुभव लें।
6. वन अधिकार दावों, पेसा और भूमि हस्तांतरण के मामलों में विशेषज्ञता विकसित करें।

प्रमुख परीक्षाएँ

- कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) — NLU में प्रवेश हेतु
- अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) — वकालत का लाइसेंस हेतु

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (NLU Jodhpur) — जोधपुर, राजस्थान (https://www.nlujodhpur.ac.in/)
- यूनिवर्सिटी फाइव इयर लॉ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय — जयपुर, राजस्थान (https://www.uniraj.ac.in/)
- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय — विधि संकाय — जोधपुर, राजस्थान (https://www.jnvu.co.in/)
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) — बेंगलुरु, कर्नाटक (https://www.nls.ac.in/)

निजी संस्थान

- मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर — स्कूल ऑफ़ लॉ — जयपुर, राजस्थान (https://jaipur.manipal.edu/)

- जगन्नाथ यूनिवर्सिटी — विधि विभाग — जयपुर, राजस्थान (https://www.jagannathuniversity.org/)

ऑनलाइन

- CLAT कंसोर्टियम ऑफ़ NLUs — तैयारी व जानकारी — ऑनलाइन (https://consortiumofnlus.ac.in/)
- SWAYAM — कानून व मानवाधिकार पाठ्यक्रम — ऑनलाइन (https://swayam.gov.in/)

फ़ीस

सरकारी विश्वविद्यालयों (राजस्थान विवि, जेएनवीयू) में LLB की फीस बहुत कम — लगभग ₹10,000–30,000 प्रति वर्ष होती है। NLU जोधपुर जैसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में यह लगभग ₹2–3 लाख प्रति वर्ष और निजी लॉ कॉलेजों में ₹1–4 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों को शुल्क माफ़ी व छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है।

छात्रवृत्तियाँ

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- अनुसूचित जनजाति हेतु पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (जनजातीय कार्य मंत्रालय) (https://tribal.nic.in/Scholarship.aspx)
- SJE राजस्थान — छात्रवृत्ति योजनाएं (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- Buddy4Study — विधि/लॉ छात्रवृत्तियां (https://www.buddy4study.com/)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

ज़िला व उच्च न्यायालय, विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA/DLSA), आदिवासी अधिकार व मानवाधिकार NGO, ग्राम सभाएं, अनुसूचित (Scheduled) क्षेत्र और वन-ग्रामों में क्षेत्रीय दौरे।

कार्य-संस्कृति

काम में अदालत की पैरवी के साथ-साथ गाँवों में दौरे, दावों का दस्तावेज़ीकरण और समुदाय के साथ संवाद शामिल है। घंटे अनियमित हो सकते हैं और शुरुआती वर्षों में आय सीमित रहती है, पर यह गहरे संतोष और सामाजिक प्रभाव वाला काम है। आदिवासी समुदाय की गरिमा और सहमति का सम्मान इस पेशे का मूल है।

कौन नौकरी देता है

- राष्ट्रीय व राज्य/ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA/SLSA/DLSA)
- मानवाधिकार संगठन और सार्वजनिक हित विधिक (PIL) फर्में
- जनजातीय कार्य मंत्रालय व राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (विधिक सलाहकार)
- आदिवासी व वन अधिकार पर काम करने वाले NGO और जन-संगठन
- स्वतंत्र वकालत — ज़िला/उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में
- विधि विश्वविद्यालयों के विधिक सहायता क्लिनिक व शोध केंद्र

माँग (2026)

देश में लाखों आदिवासी परिवारों के वन अधिकार दावे अब भी लंबित हैं, भूमि हस्तांतरण, विस्थापन और झूठे मुकदमों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए वन अधिकार अधिनियम और पेसा में दक्ष अधिवक्ताओं की माँग बनी हुई है। राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी बहुल ज़िलों (उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़) और देशभर के अनुसूचित क्षेत्रों में विधिक सहायता की गहरी ज़रूरत है, हालांकि यह मुख्यतः उद्देश्य-प्रेरित क्षेत्र है, बड़े वेतन वाला नहीं।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. जूनियर अधिवक्ता (वरिष्ठ वकील/विधिक सहायता संस्था के साथ)
2. स्वतंत्र अधिवक्ता — आदिवासी/वन अधिकार मामलों में विशेषज्ञ
3. उच्च न्यायालय अधिवक्ता / NGO का विधिक निदेशक
4. वरिष्ठ अधिवक्ता, सार्वजनिक हित याचिका (PIL) विशेषज्ञ या नीति-सलाहकार

कमाई

शुरुआत	₹15,000–30,000/माह
मध्य स्तर	₹40,000–80,000/माह
वरिष्ठ स्तर	₹1,00,000+/माह

यह एक ईमानदार अनुमान है: शुरुआती जूनियर अधिवक्ता की आय सीमित (₹15,000–30,000/माह) रहती है और विधिक सहायता/अधिकार-वकालत का काम प्रायः उद्देश्य-प्रेरित होता है। अनुभव, प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रैक्टिस के साथ आय बढ़ती है; NALSA/DLSA पैनल अधिवक्ताओं को मामलेवार मानदेय मिलता है। कई प्रसिद्ध आदिवासी-अधिकार वकील बड़ी कमाई के बजाय न्याय और समुदाय-सेवा को प्राथमिकता देते हैं।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- आदिवासी समुदायों के जीवन और अधिकारों पर सीधा, सार्थक प्रभाव
- संविधान, वन अधिकार अधिनियम व पेसा जैसे मज़बूत कानूनों का सहारा
- समाज में सम्मान और गहरा व्यक्तिगत संतोष

चुनौतियाँ

- शुरुआती वर्षों में सीमित व अनिश्चित आय
- लंबी अदालती प्रक्रिया, ज़मीनी दौरे और मानसिक-शारीरिक थकान
- कभी-कभी दबाव, विरोध या सुरक्षा जोखिम का सामना

9 असल ज़िंदगी की कहानियाँ

Palla Trinadha Rao
अधिवक्ता व आदिवासी भूमि-अधिकार विशेषज्ञ, आंध्र प्रदेश/तेलंगाना

डॉ. पल्ला त्रिनाध राव एक अधिवक्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि-अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया है। वे वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेसा के क्रियान्वयन पर गहन कानूनी कार्य व शोध करते हैं, आदिवासियों की ज़मीन गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित होने (लैंड एलियनेशन) के विरुद्ध पैरवी करते हैं, और जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए वन अधिकारों के 'वादे और प्रदर्शन' पर हैंडबुक तैयार करने में योगदान दिया है। उनकी कहानी दिखाती है कि कानून की शिक्षा को ज़मीनी अधिकारों की लड़ाई का औज़ार बनाकर एक अधिवक्ता वंचित समुदायों के लिए स्थायी बदलाव ला सकता है।

Down To Earth · https://www.downtoearth.org.in/author/palla-trinadha-rao

Shalini Gera
मानवाधिकार वकील व सह-संस्थापक, जगदलपुर लीगल एड ग्रुप (JagLAG), बस्तर

शालिनी गेरा एक मानवाधिकार वकील हैं जिन्होंने जगदलपुर लीगल एड ग्रुप (JagLAG) की सह-स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा और बीजापुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को मुफ़्त विधिक सहायता देता है। उन्होंने और उनकी साथी वकीलों ने उन आदिवासियों की पैरवी की जिन पर झूठे आरोप, अवैध हिरासत और अत्याचार के मामले थे, और इस दुर्गम क्षेत्र में वकालत का अधिकार पाने के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो कानून को आदिवासी समुदायों की गरिमा और न्याय की रक्षा का माध्यम बनाना चाहती हैं।

Front Line Defenders · https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/shalini-gera

10 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- जनजातीय संपर्क अधिकारी
- जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता
- जनजातीय पर्यावरण संरक्षण अधिकारी

11 स्रोत व आगे पढ़ें

1. राजस्थान करियर गाइडेंस – जनजातीय विधिक अधिवक्ता — https://cg.rajasthan.gov.in/careerguidance/hi/career/%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-tribal-legal-adv/

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय – वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 — https://tribal.nic.in/fra.aspx

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) — https://nalsa.gov.in/legal-aid/

4. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर – CLAT 2026 — https://www.nlujodhpur.ac.in/

5. वन अधिकार अधिनियम (विकिपीडिया) — https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_Rights_Act_(India)

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in